

(माननीय न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, जे)

माननीय न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल- एसीजे और अजय कुमार मित्तल, जे. के समक्ष

लखविंदर सिंह - अपीलकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य, - उत्तरदाता

Civil Writ Petition No. 9315 of 2011

25 मई 2011

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद. 14, 19, 21, 22, 22(4) और 226/227- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम, 1985- धारा 37- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 167(2), 309 एवं 433- भारतीय दंड संहिता धारा 302- याचिकाकर्ता को 3 किलोग्राम अफीम रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया- याचिकाकर्ता मुकदमे के दौरान हिरासत में था- जमानत आवेदन वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया- तर्क है कि हिरासत में बने रहना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37, सीआरपीसी की धारा 167(2) और 309 याचिकाकर्ता को 90 दिनों से अधिक हिरासत में रखे बिना चुनौती दी गई घोषणा संविधान की धारा 22(4) का उल्लंघन है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, जिसे बिना प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, जमानत आवेदन की अस्वीकृति के परिणामस्वरूप गैर- जमानती मामले में हिरासत जारी रखने को भारत सरकार बनाम राम समाजुह (1999) 9एससीसी 429, दादू बनाम महाराष्ट्र राज्य (2000) आरएससीसी 437 और बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684 के आधार पर अनुच्छेद 21 के साथ असंगत नहीं माना जा सकता है। धारा 37 को संवैधानिक माना गया। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह कि नशीली दवाओं से संबंधित व्यक्ति कई निर्दोष युवा पीड़ितों को मौत का झटका देने में सहायक हैं, जिसके लिए सीआरपीसी की धारा 167(2) की वैधता की जांच करना आवश्यक था। पी.सी. इसे भी बरकरार रखा गया क्योंकि यह जांच को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है और किसी व्यक्ति को जमानत नहीं मिलने पर उसे हिरासत में रखने के लिए कानूनी प्राधिकरण का भी प्रावधान है। याचिका खारिज कल्याण चंद्रा के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 309 को भी अवैध नहीं ठहराया जा सकता।

(पैरा 6, 7, 8, 9 & 10)

यह याचिका यह घोषित करने की मांग करती है कि याचिकाकर्ता को विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में रखना अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 का उल्लंघन है। यह भी

घोषणा की गई है कि नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम की धारा 37। 1985 (बाद में इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) और 309 अत्यंत अधिकारहीन हैं। आगे घोषणा की मांग की गई है कि याचिकाकर्ता को 90 दिनों से अधिक हिरासत में रखना अनुच्छेद 22(4) का उल्लंघन है। संविधान

(2) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे एफआईआर संख्या 407, दिनांक 8 नवंबर, 2009 के संबंध में अधिनियम की धारा 18/29/61 के तहत गिरफ्तार किया गया है और इस आरोप पर मुकदमा लंबित रहने तक हिरासत में रखा गया है कि उसने स्व. 3 किलोग्राम के कब्जे से मिला। अफीम का. याचिकाकर्ता ने सीआरएल दाखिल कर जमानत के लिए आवेदन किया। इस न्यायालय में 2011 का एम. नं. 1049- एम जिसे वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया, जैसा कि याचिका के पैरा 16 में बताया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता अभी भी हिरासत में है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

(3) हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है।

(4) याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि मुकदमे के दौरान किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है और उसे दोषसिद्धि के बाद ही हिरासत में रखा जा सकता है जैसे कि वह निर्दोष पाया गया हो। कानून के तहत अवैध हिरासत के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। हिरासत प्रक्रिया की निष्पक्षता के सिद्धांत के खिलाफ होगी और प्रक्रिया जो बिना दोषसिद्धि के हिरासत की अनुमति देती है वह एक नागरिक के लिए कठोर है। केरल राज्य बनाम रानीफ, (1) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिल नायडू राज्य (2) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में, आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ में निर्धारित प्रत्यक्ष प्रभाव परीक्षण या "अधिकार परीक्षण" ( 3) इस प्रकार दोहराया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन की वैधता का परीक्षण न केवल अनुच्छेद 21 के तहत बल्कि अनुच्छेद 14 और 19 के तहत भी किया जा सकता है।

(5) हम निवेदन स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

(6) निस्संदेह, एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के तहत प्रदत्त एक पोषित मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना ऐसे अधिकार से वंचित नहीं

(1) (2011 ) 1 SCC 784

(2) AIR 2007 SC 861

(3) AIR 1970 SC 564

(माननीय न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, जे)

किया जा सकता है और प्रक्रिया न्यायसंगत होनी चाहिए। निष्पक्ष और उचित जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत अधिकारों के संदर्भ में परीक्षण किया जा सकता है। साथ ही, जमानत आवेदन की अस्वीकृति के परिणामस्वरूप गैर- जमानती अर्थ में हिरासत में एक विचाराधीन कैदी को हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के अनुरूप नहीं माना जा सकता है और न ही हिरासत को निष्पक्ष प्रक्रिया का उल्लंघन माना जा सकता है और इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अनुरूप। कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन (4) मामले में इस मामले से निपटते हुए देखा गया।

"18. यह सही है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक संवैधानिक गारंटी है। हालाँकि, अनुच्छेद 21 जो उपरोक्त अधिकार की गारंटी देता है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने पर भी विचार करता है . इस देश के आपराधिक कानूनों के तहत, गैर- जमानती अपराधों के आरोपी व्यक्ति को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान हिरासत में रखा जा सकता है, जब तक कि उसे कम के अनुसार जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है। इस तरह की हिरासत पर उल्लंघनात्मक होने के रूप में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का क्योंकि यह कानून द्वारा अधिकृत है। लेकिन गैर- जमानती अपराधों के आरोपी व्यक्ति भी जमानत के हकदार हैं यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहा है और/ या यदि अदालत दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बावजूद ऐसे व्यक्तियों को जमानत पर रिहा करने की आवश्यकता है जहां तथ्यात्मक परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक हो। उस प्रक्रिया में जिस व्यक्ति की जमानत के लिए आवेदन एक बार खारिज कर दिया जाता है, उसे तथ्यात्मक स्थिति में बदलाव होने पर जमानत देने के लिए बाद में आवेदन दाखिल करने से नहीं रोका जाता है। ऐसे मामलों में यदि तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक हो, भले ही उनके पहले आवेदन खारिज कर दिए गए हों, तो अदालतें ऐसा कर सकती हैं, (जोर दिया गया है)।

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में जमानत के प्रावधानों की तुलना में जमानत देने के मामले में अधिक कठोर है। इसके उद्देश्य पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम राम समुझ (5) मामले में विचार किया था और यह माना गया कि उक्त प्रावधान को नारोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की तस्करी और ऐसी दवाओं और पदार्थों की अवैध तस्करी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और खत्म करने के लिए शामिल किया गया था, जिनका समाज पर हानिकारक प्रभाव और घातक प्रभाव था। यह देखा गया कि नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले

(4) (2005) 2 SCO 42

(5) (1999) 9 SCC 429

व्यक्ति कई निर्दोष युवा पीड़ितों को मौत का झटका देने में सहायक हैं, जिसकी जाँच करना आवश्यक था। उसमें प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

"6. उपरोक्त अनुभाग 1988 के बिल संख्या 125 को पेश करने के लिए उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उल्लिखित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया है:

"भले ही बड़े अपराध सजा के स्तर के आधार पर गैर- जमानती हैं, तकनीकी आधार पर, ड्रग अपराधियों को जमानत पर रिहा किया जा रहा था। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के प्रवर्तन में आने वाली कुछ कठिनाइयों के मद्देनजर कानून को और मजबूत करने के लिए इसमें संशोधन की जरूरत महसूस की गई है।" (जोर दिया गया)

7. यदि यह ध्यान में रखा जाए कि उपरोक्त विधायी अधिदेश का पालन और अनुसरण किया जाना आवश्यक है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक हत्या के मामले में, आरोपी एक या दो व्यक्तियों की हत्या करता है, जबकि वे व्यक्ति जो नशीली दवाओं का कारोबार करते हैं, मौत का कारण बनने या कई निर्दोष युवा पीड़ितों को मौत का झटका देने में सहायक होते हैं। जो असुरक्षित हैं यह समाज पर हानिकारक प्रभाव और घातक प्रभाव डालता है, वे समाज के लिए खतरा हैं; भले ही उन्हें अस्थायी रूप से रिहा कर दिया जाए, पूरी संभावना है कि वे तस्करी और/ या गुप्त रूप से नशीले पदार्थों का कारोबार करने की अपनी नापाक गतिविधियों को जारी रखेंगे। इसका कारण बड़ी हिस्सेदारी और इसमें शामिल अवैध लाभ हो सकता है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत सजा के संबंध में विवाद से निपटते हुए इस न्यायालय ने संक्षेप में कहा है ड्रग्स डिडिएर बनाम मुख्य सचिव, केंद्र शासित प्रदेश गोवा, (1990) आईएससीसी 95 में ऐसी गतिविधियों का प्रतिकूल प्रभाव निम्नानुसार है (एससीसी पी. 104, पैरा 24)।

'24. गहरी चिंता के साथ, हम यह बता सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड की संगठित गतिविधियों और इस देश में मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की गुप्त तस्करी और ऐसी दवाओं और पदार्थों की अवैध तस्करी के कारण जनता के एक बड़े वर्ग में नशीली दवाओं की लत लग गई है। विशेष रूप से दोनों लिंगों के किशोरों और छात्रों में यह समस्या हाल के वर्षों में गंभीर और चिंताजनक रूप धारण कर चुकी है। इसलिए, समग्र रूप से समाज पर हानिकारक प्रभाव और घातक प्रभाव डालने वाले इस बढ़ते और तेजी से बढ़ते विनाशकारी खतरे को प्रभावी ढंग से नियंत्रित और समाप्त करने के लिए। संसद ने अपने विवेक से, अनिवार्य न्यूनतम कारावास और जुर्माने को निर्दिष्ट करते हुए 1985 के इस एसी 81 को पेश करके प्रभावी प्रावधान किए हैं।

(माननीय न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, जे)

8. बाज़ार में बढ़ती खतरनाक दवाओं के खतरे को रोकना। संसद ने प्रावधान किया है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत जघन्य अपराध के आरोपी व्यक्ति को मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए जब तक कि धारा 37 में अनिवार्य शर्तें प्रदान न की गई हों।

(i) यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, और

(ii) कि वह संतुष्ट है कि जमानत पर रहने के दौरान उसके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"

(8) पुनः दादू वर्स्टेस राज्य महाराष्ट्र (6) में इस मामले पर इस प्रकार विचार किया गया-

"4. इस धारा की शक्तियों का भारत संघ द्वारा इस आधार पर बचाव किया गया है कि चूंकि संसद के पास नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट से कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए दोषी को अपील दायर करने और रिहाई, छूट या कम्यूटेशन की मांग करने का अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य नशीली दवाओं की लत और तस्करी पर अंकुश लगाना है, जिसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक माना जाता है। मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न अवैध धन का उपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने सहित अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। मादक द्रव्य- विरोधी न्याय को सामाजिक न्याय का एक आपराधिक आयाम होने का दावा किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत में नशीली दवाओं पर वैधानिक नियंत्रण आमतौर पर कुछ केंद्रीय अधिनियमों के माध्यम से किया जा रहा था, हालांकि कुछ राज्यों ने दवाओं के अवैध व्यापार से निपटने के लिए कुछ कानून भी बनाए थे। ओपियम अधिनियम और खतरनाक औषधि अधिनियम आदि का संदर्भ दिया गया है। साइकोट्रोपिक पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 1971 द्वारा परिकल्पित तरीके से साइकोट्रोपिक पदार्थों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए व्यापक कानून की अनुपस्थिति में, इस विषय पर कुछ व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। बड़े आयामों की सामाजिक चुनौती का सामना करने की दृष्टि से। संसद ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर नियंत्रण से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को समेकित और संशोधित करने और अधिनियम के तहत बड़े हुए दंड का प्रावधान करने के लिए अधिनियम बनाया। यह अधिनियम बड़े हुए और कड़े दंड का प्रावधान करता है। दावा किया जाता है कि आपत्तिजनक धारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने और अवैध तस्करी के खतरे को रोकने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यह धारा न केवल संहिता की धारा 433 के तहत कार्यपालिका की शक्ति को छीनने के लिए अधिनियमित की गई थी, बल्कि संहिता के तहत निलंबित करने, हटाने या हटाने की शक्ति भी छीनने के लिए बनाई गई थी। अधिनियम के तहत पारित सजाओं

को परिवर्तित करें। अधिनियम के तहत कन्विएट्स को संविधान में निहित समानता की गारंटी का उल्लंघन किए बिना भेदभाव को उचित ठहराने वाला एक वर्ग बताया गया है। अनुभाग की संवैधानिक वैधता का समर्थन करना। उत्तरदाताओं ने इस विषय पर लोकसभा की बहस पर भी भरोसा किया है।

XX

XX

XX

XX

XX

XX

15...धारा के तहत कार्यकारी पर लगाया गया प्रतिबंध एक उचित उद्देश्य और धारा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए प्रतीत होता है। संशोधन विधेयक पेश करते समय। जिसमें धारा 32-ए शामिल थी. 16 दिसंबर को संसद में. 1988 में वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि देश अवैध दवाओं के पारगमन की समस्या का सामना कर रहा है जो हाल के दिनों में बढ़ गई है। ऐसी ट्रॉली से रिसाव के कारण दुरुपयोग और जोड़ की समस्याएँ पैदा हो रही थीं। सरकार बढ़ती नशीली दवाओं की स्थिति से चिंतित थी जिसके लिए कई विधायी, प्रशासनिक और निवारक उपाय किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप काफी हद तक यातायात की जाँच और पारगमन हुआ। हालाँकि, आंतरिक नशीली दवाओं की तस्करी में वृद्धि, अवैध उत्पादक क्षेत्रों से अफीम की निकासी और देश के भीतर दवाओं के अवैध निर्माण के प्रयासों ने उठाए गए जवाबी उपायों के प्रभाव को कमजोर करने की धमकी दी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान वाले गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र और बर्मा वाले गोल्डन ट्राइंगल क्षेत्र से मादक पदार्थों की तस्करी के खतरे की भयावहता को ध्यान में रखते हुए। थाईलैंड और लाओस और आंतरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 4 अप्रैल, 1988 को तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक नई पहल के रूप में 14-सूत्रीय निर्देश जारी किया गया था...

(9) बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (7) में, आर.सी. में कानून के विकास पर विचार करते हुए। कूपर, यह देखा गया:

“61.... यथोचित या तर्कसंगत रूप से यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) में उल्लिखित कोई भी अधिकार हत्या करने की स्वतंत्रता या, किसी भी तरह का अपराध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसलिए, दंडात्मक कानून, यानी ऐसे कानून जो अपराधों को परिभाषित करते हैं और अपराध करने के लिए सजा निर्धारित करते हैं, उन पर अनुच्छेद 19(1) लागू नहीं होता है। निःसंदेह, हम यह नहीं कह सकते कि दंडात्मक कानूनों का उद्देश्य आम तौर पर ऐसा है कि इसमें कोई भी शामिल नहीं है बैंक राष्ट्रीयकरण मामले में इस न्यायालय के निर्णय के बाद अनुच्छेद 19(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन। (1970) 1एससीसी 248. सिद्धांत, कि राज्य की कार्रवाई का उद्देश्य और स्वरूप अकेले ही उस सुरक्षा की सीमा निर्धारित करता है जिसका दावा किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है और व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर राज्य की कार्रवाई का प्रभाव अप्रासंगिक है। बदनाम हो गया है। लेकिन मामले की बात यह है कि, सार और सार में, दंडात्मक कानून अनुच्छेद 19(1) में निहित

(माननीय न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, जे)

अधिकारों के विषय- वस्तु से संबंधित नहीं हैं। यह फिर से अनुच्छेद 19 की प्रयोज्यता पर निर्णय लेने के उद्देश्य से पर्याप्त नहीं है क्योंकि जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा तैयार किए गए परीक्षण से पता चलता है, भले ही कोई कानून, अपने सार और सार में, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार से निपटता नहीं है। (1), यदि कानून का प्रत्यक्ष और अपरिहार्य प्रभाव उन अधिकारों में से किसी को कम या निरस्त करने जैसा है, तो अनुच्छेद 19(1) आकर्षित होगा। तब किसी दंडात्मक कानून की वैधता को भी थाई अनुच्छेद की कसौटी पर परखना आवश्यक हो जाएगा। मामले के इस बाद वाले पहलू पर, हमारी राय है कि दोषसिद्धि और सजा के आदेश के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता से वंचित होना दंडात्मक कानून का प्रत्यक्ष और अपरिहार्य परिणाम नहीं है, बल्कि दोषसिद्धि और सजा के आदेश के लिए केवल आकस्मिक है जो हो सकता है या चलन में नहीं आ सकता, यानी जो पारित हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए हमारे द्वारा तैयार किए गए परीक्षण को इसके दोहरे पहलू में ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि दंड संहिता की धारा 302 को संविधान के अनुच्छेद 19(1) की कसौटी पर खरा नहीं उतरना है।

62. यह विशेष रूप से उन अपराधों के लिए सच है, जो स्वाभाविक रूप से शांति और दुर्भावनापूर्ण हैं, जिन्हें अंग्रेजी आम कानून के तहत अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो कि अपराधों से अलग थे। बलात्कार, आगजनी, चोरी. चोरी (डकैती और डकैती); जबकि अपराध कानून द्वारा निषिद्ध चीजों को दूसरों के अधिकारों पर आघात के रूप में स्वीकार करते हैं। हालाँकि ऐसे अपराधों से कोई नैतिक अधमता नहीं जुड़ती। ऐसी हरकतें केवल इसलिए अपराध बनते हैं क्योंकि वे निषिद्ध हैं। जबकि अपराध धारा 19(1) के तहत सीधे या अनिवार्य रूप से अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। अपराधों की अन्य श्रेणी के तहत ऐसे मामले संभव हैं जहां उनसे संबंधित कानून सीधे तौर पर ऐसे अधिकारों को प्रतिबंधित या कम कर देता है। श्री सोराबजी द्वारा दिये गये दृष्टान्त से बात स्पष्ट हो जायेगी। मान लीजिए, एक कानून बनाया गया है जो यह प्रावधान करता है कि कानून द्वारा स्थापित सरकार की किसी भी तरह की आलोचना करना एक अपराध होगा और ऐसे अपराध के लिए सजा के रूप में पांच साल की कैद का प्रावधान करने का एक और प्रावधान करता है। ऐसा कानून (अर्थात् अपराध को परिभाषित करने वाला इसका प्रावधान) सीधे और अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 19(1) के खंड और खंड (ए) के तहत गारंटीकृत अधिकार का हनन करेगा। इसलिए, वैध होने के लिए, इसे अनुच्छेद के खंड (2) में सन्निहित तर्कसंगतता की परीक्षा पास करनी होगी। लेकिन दंड संहिता के उन प्रावधानों के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता जिनसे हम चिंतित हैं।"

(10) उपरोक्त के मददेनजर, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि अधिनियम की धारा 37 असंवैधानिक है। जहां तक धारा 167(2) सीआरपीसी का संबंध है। पी.सी., वही जांच के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड का प्रावधान करता है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए और किसी व्यक्ति को जमानत नहीं मिलने पर उसे हिरासत में रखने के लिए कानूनी प्राधिकरण प्रदान करने के लिए ऐसा प्रावधान आवश्यक है। इसी

प्रकार धारा 309 सीआरपीसी मुकदमे के दौरान किसी व्यक्ति को हिरासत में भेजने का प्रावधान करने वाले पीसी को कल्याण चंद्रा में दिए गए कानून के मद्देनजर अमान्य नहीं माना जा सकता है, सलाहकार

916

एल.आई.आर. पंजाब और हरियाणा

2011(2)

बोर्ड की राय की आवश्यकता वाले संविधान के अनुच्छेद 22 (4) केवल निवारक हिरासत के लिए लागू होते हैं, हिरासत के लिए नहीं। किसी अपराध की सुनवाई के दौरान. इस प्रकार, किसी ऐसे विचाराधीन कैदी की निरंतर हिरासत को अवैध घोषित करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसकी जमानत खारिज कर दी गई है।

(11) तदनुसार, हमें इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली। उसी को खारिज किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने मामले के गुण- दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।'

---

एम. जैन

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा